



जदयू ने भाजपा को चुनौती/धमकी दी कि नीतीश को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें अन्यथा ...

जदयू की अप्रत्यक्ष धमकी यह है कि अगर चुनाव के नतीजों तक का इन्तजार करेगी भाजपा तो उस समय तो सभी स्वतंत्र होंगे नई परिस्थितियों में नए समीकरण ढूंढने के लिये

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर की खामोशी बुधवार को उस समय और गहरा गई, जब जनता दल (यूनाइटेड) जेडीयू ने अपने बड़े सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे।

जेडीयू नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाशिये पर धकेलने और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान जैसे अन्य सहयोगियों को टिकट वितरण में बढ़ावा देने की सुनियोजित कोशिश कर रही है।

पार्टी के सूत्रों ने बताया कि हालांकि जेडीयू ने यह मांग औपचारिक रूप से

- यह उल्लेखनीय है कि जदयू ने यह धमकी देने के लिए शायद राजनीतिक कारणों से प्रेस कॉन्फ्रेंस का रास्ता नहीं चुना है।
- पर जदयू के खेमे में इस मुद्दे पर कई सप्ताह से बहस छिड़ी हुई है कि भाजपा सुनियोजित तरीके से काफी अरसे से नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है।
- यह भी महसूस किया जा रहा है कि भाजपा में काफी हिचकिचाहट है नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बारे में।
- जदयू के कार्यकर्ता और नेता यह मानते हैं कि भाजपा का प्रयत्न है कि एनडीए के अन्य छोटे घटकों को, नीतीश को कमजोर करके पनपाया जाये।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाई, लेकिन भाजपा के बढ़ते दबदबे को लेकर पार्टी के भीतर कई हफ्तों से यह चर्चा चल रही थी। ताज़ा विवाद उस समय भड़का, जब भाजपा नीतीश कुमार को बिहार चुनाव अभियान में मुख्यमंत्री पद का निर्विवाद चेहरा घोषित करने की अनिच्छुक नज़र आई।

जेडीयू के वरिष्ठ एमएलसी और

प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखे शब्दों में कहा, “भाजपा यह तय नहीं कर सकती कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे लिए यह सवाल बेमानी है, क्योंकि हम कई बार दोहरा चुके हैं कि नीतीश कुमार ही राज्य के निर्विवाद नेता हैं। अपने संन्यास या उत्तराधिकारी के बारे में फैसला केवल वही करेंगे।”

नीरज कुमार के ये बयान इस बात

की ओर इशारा करते हैं कि जेडीयू में भाजपा की हाल की चुनावी रणनीतियों को लेकर नाराज़गी बढ़ रही है, जिन्हें नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा की छोटी पार्टियों से नज़दीकी और टिकट वितरण पर उसके नियंत्रण ने जेडीयू नेताओं में असंतोष (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भजन गायिका मैथिली ठाकुर को भाजपा ने टिकट दिया

पटना, 15 अक्टूबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने आज 12 उम्मीदवारों की

- **भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें मैथिली ठाकुर को अलीनगर से प्रत्याशी बनाया गया है।**

दूसरी सूची जारी की। सूची के अनुसार, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर का प्रत्याशी बनाया गया है। मैथिली ठाकुर कल ही भाजपा में शामिल हुई हैं। बक्सर से पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वांगचुक की पत्नी ने “हेबियस कॉर्पस” याचिका में संशोधन किया

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता गीतांजलि जे. अंगमो को अपने पति सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एन एस ए) के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली “हेबियस कॉर्पस” (बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका) में संशोधन करने की अनुमति दे दी।

सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंबोलिया की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर, बुधवार को तय की है।

दो दिन पहले केन्द्र सरकार ने अंगमो को वांगचुक की गिरफ्तारी के आधार (ग्राउन्ड्स ऑफ डिटैशन) उपलब्ध कराए थे।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो अंगमो की ओर से पेश हुए, ने अदालत से याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी, ताकि सरकार द्वारा दिए गए गिरफ्तारी के आधारों को उचित रूप से चुनौती दी जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वांगचुक को

यह संशोधन वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने समझाकर करवाया

- सिब्बल ने कहा कि वांगचुक ने अपनी हिरासत के सम्बंध में कुछ नोट्स बनाए थे जो वे अपने वकील को देना चाहते थे पर सरकार ने इस पर रोक लगा रखी थी।
- कपिल सिब्बल का तर्क था कि वांगचुक को ये नोट्स अपने वकील को देने का अधिकार है और इन नोट्स से केस मजबूत होगा।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नोट्स शेयर किए जाने पर सहमति दी पर कहा कि इन नोट्स से केस में देरी होती है तो उसका जिम्मेवार सरकार को नहीं ठहराया जाना चाहिए।

अपने नोट्स पत्नी के साथ साझा करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, “उन्होंने (वांगचुक) अपनी गिरफ्तारी को लेकर कुछ नोट्स बनाए हैं जिन्हें वे अपने वकील तक पहुंचाना चाहते थे। जो भी नोट्स वे तैयार करते हैं, उन्हें अपने वकील को सहायता लेने का अधिकार है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि

वे नोट्स वकील तक पहुंच सकें।”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए, ने कहा कि उन्हें नोट्स याचिकाकर्ता के साथ साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने में हुई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

श्रीलंका की प्र.मंत्री आज भारत में

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर। श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिणी अमरसुर्या गुरूवार को तीन दिन की भारत यात्रा आयेंगी। पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि श्रीलंकाई प्रधानमंत्री भारतीय

- **श्रीलंका की प्र.मंत्री डॉ. हरिणी अमरसुर्या तीन दिन के लिए भारत आयी हैं। पद ग्रहण के बाद वे पहली बार भारत आयी हैं।**

नेताओं से मुलाकात करेंगी और उनके साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगी।

श्रीलंकाई प्रधानमंत्री यहां एक निजी टेलीविजन चैनल और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगी। शिक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रही डॉ. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर सेशन कोर्ट में बम की सूचना से अफरातफरी मची

जयपुर, 15 अक्टूबर। बनीपाक स्थित जयपुर सेशन कोर्ट में बुधवार सुबह बम होने की सूचना से हड़कम्प मच गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कोर्ट परिसर में सच अभियान शुरू किया, जिसमें बम निरोध दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम ने पूरी बिल्डिंग को खाली करवाते हुए चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। पुलिस के सच अभियान

- **बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड टीम ने कोर्ट परिसर खाली कराके चप्पे-चप्पे की तलाशी ली।**

कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि बुधवार सुबह सेशन कोर्ट परिसर में स्थित चौथे माले की पोक्सो कोर्ट को एक ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि कोर्ट परिसर में बम लगाया हुआ है। कोर्ट रीडर ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सभी टीमों मौके पर पहुंचीं और कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमों मौके पर पहुंचीं और कोर्ट परिसर की कोने-कोने की जांच की। इस दौरान अतिरिक्त (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है दिल्ली में

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू किए गए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत यह घोषणा की

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। क्लाउड सीडिंग, जीआरएपी और ग्रीन क्रैकर (इको फ्रेंडली पटाखे) ये आदेश भले ही अलग-अलग लगें, लेकिन लक्ष्य एक ही है - दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करना।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को घोषणा की कि अगर मौसम की स्थिति अनुकूल रही तो सरकार आने वाले दो से तीन दिनों में क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा का प्रयोग करेगी। यह फैसला उस दिन के बाद आया जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के पहले चरण के तहत प्रतिबंध लागू किए, क्योंकि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयर क्वालिटी इंडेक्स-एक्यूआई) 200 के पार चला गया था।

दीवाली से एक हफ्ते पहले जीआरएपी का लागू होना इस बात का

- इस बार दीवाली से एक सप्ताह पहले ही जीआरएपी लागू कर दिया गया है, इससे संकेत मिलता है कि सर्दियों में दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है।
- दिल्ली सरकार गत तीन माह से “क्लाउड सीडिंग” कराने की योजना बना रही है, पहले 4 से 11 जुलाई के बीच और फिर 30 अगस्त से 10 सितम्बर के बीच का समय तय किया गया था। पर तब मानसून की सक्रियता के कारण क्लाउड सीडिंग टाल दी गई।

संकेत है कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो सकता है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ग्रीन क्रैकर को बिन्नी और उपयोग की अनुमति दी, ताकि प्रदूषण नियंत्रण और दीवाली उत्सव के बीच संतुलन बनाया जा सके।

सिरसा ने बताया कि क्लाउड सीडिंग के लिए पायलट टेनिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा, अगर अगले दो

से तीन दिनों में मौसम अनुकूल रहा तो आईएमडी की मंजूरी के बाद तीन घंटे तक क्लाउड सीडिंग की जाएगी।

उन्होंने कहा, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सड़कों पर पुरानी गाड़ियां होने के बावजूद, इस साल हमें सबसे ज्यादा दिनों तक साफ आसमान देखने को मिला।

दिल्ली सरकार पिछले तीन महीनों से कृत्रिम वर्षा कराने की योजना बना

रही थी। शुरुआत में योजना थी कि 4 से 11 जुलाई के बीच क्लाउड सीडिंग की जाए, लेकिन मानसून के दौरान जब प्रदूषण का स्तर कम होता है, तब कृत्रिम वर्षा कराने के बिचार की आलोचना हुई। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग के लिए मानसूनी बादलों की आवश्यकता होती है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे की सिफारिशों के बाद यह योजना आगे बढ़ाई गई और 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच का समय तय किया गया।

क्लाउड सीडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस जैसी विशेष सामग्रियाँ डाली जाती हैं ताकि कृत्रिम रूप से वर्षा या हिमपात कराया जा सके। इसका उपयोग पानी की कमी, कम हिमपात, या ओले और धुंध कम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में “ग्रीन” पटाखों से मनेगी दीवाली

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने दीपावली के त्योहार के दौरान 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिन्नी और उसे फोड़ने

- **सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक “ग्रीन” पटाखे चलाने की अनुमति दी है।**

की बुधवार को अनुमति दी।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अन्य की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा, हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। अदालत ने यह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

अतिथि जिसका अन्न खाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। –अथर्ववेद

आहार के छह महत्वपूर्ण घटक साधिये अन्य स्वतः मिलते रहेंगे



डॉ. सुबोध अग्रवाल

सीधे-सीधे शब्दों में बात की जाएं तो सरकार और आम जन के बीच सीधा संवाद कायम करने में भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। यही कारण है प्रशासन की भाषा में और साहित्य या इससे इतर भाषा में अंतर होता है। प्रशासन की भाषा में स्पष्टता और सहजता पहली शर्त है। इसके साथ ही प्रशासन की भाषा में जो टिप्पणी आदि होती है या यों कहें कि प्रशासकीय कार्य में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संक्षिप्त, सारगर्भित और सहजता से समझ में आने वाली होनी चाहिए जहां एक और साहित्य या साहित्य से इतर भाषा का प्रयोग होता है उसमें भाषा सौंदर्य पर बल दिया जाता है। शब्दों के प्रयोग करते

समय कहावत-मुहावरें, प्रयोगवाची शब्दों का प्रयोग, अनेकार्थक व कहीं कहीं क्लिष्ट शब्दों, व्यंग, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति या पुनरुक्ति को भाषा सौष्ठव के हिसाब से अच्छा माना जाता है और उसमें भाषा सौंदर्य भी झलकता है पर उसे किसी भी परिस्थिति में प्रशासन की भाषा के रुप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

चूंकि भाषा सरकार और आमजन के बीच सीधा संवाद कायम करने का माध्यम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिन्दी को बढ़ावा देने में सिनेमा, दूरदर्शन और अब चैनलों पर प्रसारित श्रृंखलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई है। समाचार पत्रों की भी एक समय बड़ी भूमिका रही है पर आज मीडिया में जिस भाषा का प्रयोग किया हो रहा है उसमें हिंग्लिस या यों कहें कि भाषा के प्रयोग के समय जो सतर्कता बरती जानी चाहिए रह खो गई है। एक समय समाचार पत्रों से भाषा का संबन्धन होता था, लोग सीखते थे। पर अब भाषा के प्रति गंभीरता कम होती जा रही है।

यह विषयांतर इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आज दुनिया के देशों में हिन्दी लोकप्रिय होती जा रही है। विदेशों में रहने वाले करोड़ों भारतीय हिन्दी का प्रचुरता से प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया के 200 से अधिक विश्व विद्यालयों में हिन्दी भाषा का अध्ययन-

भाषाओं और लिपियों पर भी देखा जा सकता है। आजादी के बाद भारत में संविधान निर्माताओं ने हिन्दी का महत्व समझते हुए उसे राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में अंगीकार करने की व्यवस्था की थी। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की गई कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी यहां की राजभाषा होगी।

संविधान के अनुच्छेद 351 में इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गये हैं। इन निर्देशों के अनुसार 'हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि कर उसका विकास करना ताकि वह भारतीय संस्कृति के समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।' स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में अंग्रेजी का प्रयोग 1965 तक जारी रखने व हिन्दी को विकसित रूप प्रदान करने की व्यवस्था थी। भाषा के प्रश्न पर 1965 में खर आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग ने हिन्दी का

प्रयोग बढ़ाने की सिफारिश के साथ ही अंग्रेजी का प्रयोग 1965 के बाद भी जारी रखने की सिफारिश की। वर्ष 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम पास कर यह व्यवस्था की कि संघ के जिन कार्यों के लिए 26 जनवरी, 1965 से पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था उनके लिए हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है।

हिन्दी की अपनी एक समृद्ध शब्द संपदा रही है। पर आज धीरे-धीरे हिन्दी हिंग्लिस का रूप लेती जा रही है। नए नए शब्द हिंदी के शब्दकोशों में और भी जुड़ते जा रहे हैं। हिन्दी के विकास की नई दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और भाषा को नए-नए शब्द और अर्थ मिले हैं। हिन्दी शब्दसागर के 11 भागों में लगभग 2 करोड़ 11 लाख 50 हजार शब्द उपलब्ध हैं। विभिन्न राज्यों ने शब्दावली के निर्माण का कार्य किया है और उसके द्वारा बनाए गए अनेक कोश, शब्द संग्रह अथवा शब्द संकलन निरंतर प्रयोग में आ रहे हैं। भले ही बोलचाल की भाषा में कुछ भी प्रयोग हो रहे हो पर लिखने-पढ़ने में भाषा की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए।

—**डॉ. सुबोध अग्रवाल,**
(आईएसएस)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार

प्रवासी दृष्टि: समाज, संस्कृति और सोच



डॉ. पंकज राजवंशी

मुंबई के जुहू में, जब मैं प्लसाइड से होटल के बाहर समुद्र की तरफ देख रहा था, तो मेरी निगाहें उस कंटीले तार पर बार-बार टिक रही थीं जो होटल और समुद्र के बीच शायद मेरी ही ‘सुरक्षा’ के लिए लगाया गया था। उसी तरह, जब मैं शाहरुख ख़ान के बंगले ‘मन्नत’ के बाहर पर्यटकों के झुंड के साथ उस दूसरे कंटीले तार के भीतर झोंकने की कोशिश कर रहा था, तो एक अजीब-सा विरोधाभास महसूस हुआ। बाहर खड़ी भीड़, मोबाइल स्क्रीन ऊपर उठाए, बस एक झलक पाने के लिए बेताब थी। जैसे तार के उस पार देख लेने पर से जिंदगी कुछ और हो जाएगी। शायद हर आम भारतीय अपने जीवन में किसी न किसी कंटीले तार के इस पार से उस पार जाने का सपना देखता रहता है।

मुझे लगा कि यह दृश्य केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रतीक है उस गहरे विभाजन का जो अब भारतीय समाज की स्थायी बनावट बन चुका है। यह लेख किसी आर्थिक आंकड़ें या जीडीपी की कहानी नहीं है। यह कोई राजनीतिक बयान भी नहीं है। न ही यह भारत की निंदा है। यह वीर दास की ‘दो भारत’ वाली कविता से भी प्रेरित नहीं है, लेकिन इसमें भी वही दो भारत हैं, एक जो कंटीले तारों के भीतर एसी की हवा में साँस लेता है, और दूसरा जो उन्हीं तारों के बाहर धूप में पसीना बहाता है। यह उन जिंदगियों की बात है जो आँकड़ों

के पीछे साँस ले रही हैं। मैं तीस साल पहले अमेरिका चला गया था। अब जब लौटता हूँ, तो यह फर्क और भी तीखा दिखाई देता है। अमेरिका और भारत दोनों देशों में चुनौतियाँ हैं। वहाँ भी जीवन सरल नहीं है, महँगाई है, तनाव है, स्वास्थ्य सेवाएँ महँगी हैं, लेकिन वहाँ एक ढाँचा है जो किसी भी गिरते व्यक्तित्व को थाम लेता है। भारत में अक्सर गिरने का मतलब मिट जाना होता है। मुंबई के किसी चौराहे पर खड़े होकर अगर चारों तरफ़ देखा जाए, तो ऐसा लगता है जैसे दो दुनियाएँ एक-दूसरे से कंधा छूते हुए चल रही हैं, पर एक-दूसरे की भाषा नहीं समझती। एक तरफ़ कौंच की ऊँची इमारतें हैं, जिनके लॉन में फव्वारे चखते हैं, पार्किंग में विदेशी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और जिनके अंदर जिंदगी वतानुकूलित होती है। दूसरी ओर गंग गलियों में खड़े झोपड़े हैं, जहाँ पंखेता चलना भी शायद लगजरी हो। इन दोनों दुनियाओं के बीच की भौगोलिक दूरी शायद सी मीटर भी न हो, लेकिन जीवन की गुणवत्ता में यह दूरी सदियों की लगती है। यह विरोधाभास केवल मुंबई का नहीं है। दरअसल पूरा भारत अब शायद दो चेहरों वाला हो गया है। और इन दो चेहरों के बीच की दीवार अब केवल आर्थिक नहीं, मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक भी हो चुकी है।

भारत की आबादी अब डेढ़ अरब के पास पहुँच चुकी है। इतनी बड़ी जनसंख्या ऊर्जा और सम्भावनाओं का ख़ोत हो सकती थी, अगर उसे समान अवसर, शिक्षा और सुरक्षा मिलती। आर्थिक विकास के आँकड़े ऊपर जा रहे हैं, लेकिन नीचे जिंदगी कहीं नहीं जा रही। या तो सब वही अटक ही हुई है, या ओर नीचे खिसक रही है। अमेरिका की आबादी भारत की तुलना में एक-तिहाई भी नहीं है। वहाँ भी गरीबी है, लगभग 15 प्रतिशत, पर वहाँ गरीब को जीने की बुनियादी गारंटी मिलती है। भारत में गरीब को बस जिंदा रहने की कोशिश करने का हक़ मिलता है। वह भी तब, जब मौसम, बीमारी और

दीवारों के बाहर की भूख, गंध, शोर अब सिर्फ़ अनुबिधा हैं, अपराधबोध नहीं। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे समाज में बदल गए हैं जहाँ सामाजिक दूरी अब स्थायी योजना बन चुकी है। दीवारें जितनी ऊँची होती हैं, संवेदनाएँ उतनी ही छोटी हो जाती हैं। निजी सुरक्षा, निजी स्कूल, निजी स्वास्थ्य, निजी सब कुछ है, और सार्वजनिक कुछ नहीं। जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए सार्वजनिक प्रणाली सिर्फ़ प्रतीक्षा की घड़ी है। भारत में अब शिक्षा भी एक विशेषाधिकार बन गई है। गरीब बच्चा सिर्फ़ इसलिए स्कूल से बाहर हो जाता है क्योंकि उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। और अगर स्कूल के बाहर नहीं भी हो, तो कम से कम शिक्षा के माध्यम और गुणवत्ता में दिन और रात का फ़र्क़ है।

भारत में अब शिक्षा भी एक विशेषाधिकार बन गई है। गरीब बच्चा सिर्फ़ इसलिए स्कूल से बाहर हो जाता है क्योंकि उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। और अगर स्कूल के बाहर नहीं भी हो, तो कम से कम शिक्षा के माध्यम और गुणवत्ता में दिन और रात का फ़र्क़ है।

यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि नीति की असफलता है। शिक्षा अब भविष्य का निर्माण नहीं, बल्कि भविष्य का अवशेष बनती जा रही है। स्वास्थ्य का हाल भी कुछ ऐसा ही है। एक बीमारी पूरे परिवार को तोड़ सकती है। सरकारी अस्पतालों में इलाज़ मिलना भाग्य की बात हो गई है और निजी अस्पतालों में दाखिला किसी जैकपॉट से साबित लगता है। अमेरिका में भी स्वास्थ्य सेवा महँगी है, पर बीमा और सामाजिक सहायता का ढाँचा फिर भी किसी हद तक काम करता है। भारत में एक छोटी सी बीमारी भी आर्थिक आपदा बन सकती है। नानावटी अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के वेटॉरूम में, जहाँ मैं शौकिया अपना पेट का एमआरआई करवा रहा था और 35,000 रुपये खर्च कर रहा था, वहीं मेरे पास बेंटो लेग न जाने क्या बेचकर वहीं पहुँचे थे।

इसी तरह अगर अपराध के आँकड़ों की बात करें तो अमेरिका में हिंसक अपराध ज़्यादा हैं, पर भारत में भूख, बेरोज़गारी और असुरक्षा का डर कहीं महारूढ़ तब बेटा है। वहाँ डर गोली का होता है, यहाँ डर इस बात का कि कल खाना कहाँ से आएगा। क्या यही कारण तो नहीं कि दिल्ली में हिंसक

अपराध मुंबई की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं? कंटीले तारों के बाहर जीवन जीने का डर भारतीय जीवनशैली का हिस्सा बन गया है। एक ऐसा डर जो सपनों को छोटा कर देता है, बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर लगवा देता है, और पूरे समाज की कल्पना शक्ति को सीमित कर देता है। हमने आर्थिक विकास को केवल इमारतों की ऊँचाई और मॉल की चमक में देखना सीख लिया है। पर हम भूल गए हैं कि असली विकास वह है जो नीचे खड़े व्यक्ति को सुरक्षा और गरिमा दे सके। जब तक एक ही शहर में दो अलग-अलग दुनियाएँ एक-दूसरे से मुंह चुराकर जिएँगी, तब तक कोई भी ‘नया भारत’ वाकई नया नहीं कहलाएगा।

क्या इस ख़ाई को भरने का कोई मॉडल है? शायद नहीं। या शायद बहुत सारे हैं, लेकिन इच्छाशक्ति नहीं है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि किसी देश की सफलता तब तक अधूरी है जब तक उसकी सड़कों पर भूख चलती है। हमें विकास की तेज़ रफ्तार से ज़्यादा ज़रूरत है समानता की गति की। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हर दीवार अपने आप में असफलता की निशानी है, तब तक हम सिर्फ़ बिल्डिंग बनाएँगे, समाज नहीं।

हर बार जब मैं अमेरिका से लौटकर भारत की हवा में नमक और धूल की वह जानी-पहचानी गंध महसूस करता हूँ, तो यही सोचता हूँ कि यह देश दो दुनियाओं का नहीं होना चाहिए। यह वह जगह होनी चाहिए जहाँ एक बच्चा, चाहे वह झुग्गी में जन्मा हो या किसी ग्लास टॉवर में, एक जैसा सपना देख सके और उस सपने को छू भी सके। पर शायद हमने तय कर लिया है कि दीवारें ही हमारी सबसे स्थायी वास्तुकला हैं। और इन दीवारों के भीतर हम अपने मन को सुरक्षित मानते हैं, बाहर की संकल्पों से अनजान या फिर उसे अनदेखा करते हुए।

—**डॉ. पंकज राजवंशी,**
सिफ़्टल (अमरीका) में रह रहे एक गैस्ट्रूएण्टोलॉजिस्ट हैं।

सिंचाई के पानी की चोरी रोकने की मांग

नोहर, (निसं) सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली के सी ग्रुप रेगुलेशन के दौरान भादरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही सिंचाई पानी चोरी को रोककर नोहर क्षेत्र में रासलाना वितरिका नहर टेल पर सिंचाई पानी पहुंचाने की मांग को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, किसान संगठन के पदाधिकारियों एवं जगपक्क किसानों ने मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर, मुख्य अभियंता को पत्र प्रेषित किये हैं।

पत्रों में बताया गया है कि वर्तमान में रेगुलेशन निर्धारण कमेटी अतिरिक्त

जिला क्लेक्टर, नोहर की अध्यक्षता में गठित है, जबकि जिला क्लेक्टर, हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए। चूंकि सी ग्रुप का रेगुलेशन रासलाना की आरडी 40-46 किमी से प्रारम्भ होता है तथा राजस्थान की सीमा में सिद्धमुख फीडर 24 किमी तथा रासलाना वितरिका में 40 किमी दूरी तय करने के कारण तमाम चोरी तथा मोगों द्वारा अन्य लोसेज होने के कारण यह देखा गया है कि जब सीपी-5 पर 450 क्यूसेक पानी प्राप्त होता है तो लगभग 100 125 क्यूसेक पानी ही नथवानियां हैंड

पर पहुंच पाता है। अतः जब तक पानी चोरी पर पूरा अंकुश नहीं लगाया जाता है तब तक रसीत ग्रुप हेतु 450 क्यूसेक की जगह 100 क्यूसेक अतिरिक्त पानी आर्थ 550 क्यूसेक की मांग की जाये जिससे सी ग्रुप का रेगुलेशन के दौरान टेल तक पानी पहुंच सके। सी ग्रुप रेगुलेशन के दौरान ए व बी ग्रुप के लिए मुख्य नहर सिद्धमुख फीडर, रासलाना वितरिका में बने आउलेटसेसों में भी सिंचाई पानी प्रवाहित होता रहता है जो कि जल संसाधन विभाग की विफलता ही नहीं बेहद चिंताजनक भी है है इसलिए उनको सी ग्रुप रेगुलेशन

पर पहुंच पाता है। अतः जब तक पानी चोरी पर पूरा अंकुश नहीं लगाया जाता है तब तक रसीत ग्रुप हेतु 450 क्यूसेक की जगह 100 क्यूसेक अतिरिक्त पानी आर्थ 550 क्यूसेक की मांग की जाये जिससे सी ग्रुप का रेगुलेशन के दौरान टेल तक पानी पहुंच सके। सी ग्रुप रेगुलेशन के दौरान ए व बी ग्रुप के लिए मुख्य नहर सिद्धमुख फीडर, रासलाना वितरिका में बने आउलेटसेसों में भी सिंचाई पानी प्रवाहित होता रहता है जो कि जल संसाधन विभाग की विफलता ही नहीं बेहद चिंताजनक भी है है इसलिए उनको सी ग्रुप रेगुलेशन

पर पहुंच पाता है। अतः जब तक पानी चोरी पर पूरा अंकुश नहीं लगाया जाता है तब तक रसीत ग्रुप हेतु 450 क्यूसेक की जगह 100 क्यूसेक अतिरिक्त पानी आर्थ 550 क्यूसेक की मांग की जाये जिससे सी ग्रुप का रेगुलेशन के दौरान टेल तक पानी पहुंच सके। सी ग्रुप रेगुलेशन के दौरान ए व बी ग्रुप के लिए मुख्य नहर सिद्धमुख फीडर, रासलाना वितरिका में बने आउलेटसेसों में भी सिंचाई पानी प्रवाहित होता रहता है जो कि जल संसाधन विभाग की विफलता ही नहीं बेहद चिंताजनक भी है है इसलिए उनको सी ग्रुप रेगुलेशन

के दौरान रोका जाना अति आवश्यक है। पानी चोरी रोकने हेतु अधीक्षण अभियंता, वृत्त नोहर के अधीन पानी चोरी रोकथाम प्रकोष्ठ बनाया जाये या जिला कलेक्टर स्तर पर गश्ती दलों का गठन किया जाना चाहिए ताकि यथार्थ गश्ती हो सके। जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अधीक्षण अभियंता को संयुक्त कमेटी भी हो। पत्र प्रेषित करने वालों में निवर्तमान जिला लोकपाल विनोद जोगिड़, पंचायत समिति प्रधान सोहन दिल, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन एवं भारतीय किसान संघ अध्यक्ष राजेन्द्र

सिहाग, जिला परिषद सदस्य सावित्री दलीप तेतरवाल व विमला घीसाराम नायक, पंचायत समिति सदस्य मंजु सुरेन्द्र प्रताप भारी, कृष्णा जगतपाल सहायग, शारदा प्रताप साहू व मांगीलाल शर्मा, सरपंच देवीलाल रोहिल्ला, दलपतपुरा सहकारी समिति अध्यक्ष अशोक सिंह सहायग, उपसरपंच मुकेश सिहाग, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक पारोक, लक्ष्मीनारायण बेनीवाल, कृष्ण सहायग, मांगेराम बेनिवाल, राजकुमार सुथार, एडवोकेट हंसराज बेनिवाल आदि शामिल रहे।

राशिफल	
गुरुवार 16 अक्टूबर, 2025	
कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत 2०82, आश्लेषा नक्षत्र दिन 1२:42 तक, शुभ योग रात्रि 2:11 तक, विधि करण दिन 1०:36 तक, चन्द्रमा आज दिन 1२:42 से सिंह राशि में संचार करेगा।	
पंडित अनिल शर्मा	
ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरु-मिथुन, शुक्र-कन्या, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज ज्वालामुखी योग दिन 1०:36 तक है।	
श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:36 तक, चर 1०:47 से 1२:12 तक, लाभ अमृत 1२:12 से 3:०3 तक, शुभ 4:9 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 1:3० से 3:०0 तक। सूर्योदय 6:31, सूर्यास्त 5:54	

राशिफल	
शुक्रवार 17 अक्टूबर, 2025	
कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2०82, आश्लेषा नक्षत्र दिन 1२:४२ तक, शुभ योग रात्रि २:११ तक, विधि करण दिन 1०:३६ तक, चन्द्रमा आज दिन १२:४२ से सिंह राशि में संचार करेगा।	
पंडित अनिल शर्मा	
ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरु-मिथुन, शुक्र-कन्या, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज ज्वालामुखी योग दिन 1०:36 तक है। भद्रा प्रातः 1०:36 तक रहेगी।	
श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:36 तक, चर 1०:47 से 1२:12 तक, लाभ अमृत 1२:12 से 3:०3 तक, शुभ 4:9 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 1:3० से 3:०0 तक। सूर्योदय 6:३1, सूर्यास्त 5:54	



आया त्योहार हीरो पे सवार

HF. Deluxe Pro

Splendor+
XTEC 2.0



₹ 58 200[#]

~~₹ 63 133~~

GST लाभ ₹ 4 933

₹74 202[#]

~~₹ 80 491~~

GST लाभ ₹ 6 289

सीमित अवधि ऑफर

प्रतिदिन EMI
₹59^{\$}
से शुरू

डाउन पेमेंट
₹999
से शुरू

विशेष कॉर्पोरेट ऑफर्स
₹2 200~
तक



पाएं जीतने का मौका
100% कैशबैक |  **24 कैरट सोने का सिक्का**
 और कई अन्य सुनिश्चित लाभ*

Additional offers on:



Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorized outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. Offer amount and combination of offer may vary for model/variant and states and it is applicable on select models only, for a limited time period or till stock lasts. *Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. *T&C apply and offer available only on limited stores. *Limited period offer. T&C apply. As per cumulative dispatch numbers till August 2025. Ex-showroom price of Splendor+ and HF Deluxe in Rajasthan.

TOLL FREE
1800 266 0018

अधिकृत डीलर: **सवाई माधोपुर: विजय हीरो**, 9289922388, **टोंक: राजू हीरो**, 9289922438, **दौसा: अरुण हीरो**, 9289922522, **गंगापूर सिटी: पालीवाल हीरो**, 9289922842, **बांदीकुर्द: झालानी हीरो**, 9289922960, **देवली: गोयल हीरो**, 9289922995, एमोशिएट डीलर: **दौसा: धारदा हीरो**, नांगल राजावतन, 7428595934, **लालसोट: आशीष मोटर्स**, 9413326881, **कटौली: देव मोटर्स**, 7428595932, **सपोटरा: जिंदल ऑटोमोबाइल्स**, 7428598990, **महुवा: एम.एस. मोटर्स**, 7428595936, **निवाई: एस. मोटर्स**, 9414273518, **नादौती: अवस्थी मोटर्स**, 7428598989, **हिंडौन सिटी: विष्णु ऑटोमोबाइल्स**, 7469294625, **वजीरपुर: आशा मोटर्स**, 7428595931, **सिकंदरा: निरंकार मोटर्स**, 7062729676, 6377061716, **फेलिकापुरा: मोहित मोटर्स**, 9982480849, **कैलादेवी: शास्त्री मोटर्स**, 9828616188, **शिवर: शिव शक्ति मोटर्स**, 9414553872, **कुरगांव: सैनी मोटर्स**, 9828210025, **मंडावरी: अभिषेक मोटर्स**, 9413453111, **सुरौठ: श्री साई मोटर्स**, 8114494899 (Buy, Sell, Exchange Any Used Two Wheeler) **सवाई माधोपुर: विजय हीरो**, 9289922388, **गंगापूर सिटी: पालीवाल मोटर्स**, 9289922842.

राजस्थान मंडपम् व यूनिटी मॉल के खिलाफ दायर पी.आई.एल. सुप्रीम कोर्ट में खारिज

शीर्ष अदालत ने कहा कि, “जयपुर की यह विवादित भूमि, वन भूमि नहीं है और आवेदन में कोई औचित्य नहीं पाया गया है”

–कार्यालय संवाददाता–
जयपुर । सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में राज्य सरकार की दो योजनाओं राजस्थान मंडपम् व यूनिटी मॉल का निर्माण रोकने और इस जमीन को वन भूमि घोषित करने के लिए दायर पीआईएल को खारिज कर दिया। सीजेआई बी.आर.गवई व जस्टिस के. विनोद चन्द्रन ने यह आदेश टी.एन. गोदावर्मन मामले में दायर एक पीआईएल पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित भूमि वन भूमि नहीं है और आवेदन में कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि जयपुर की सांगानेर तहसील स्थित डोल का बाड़ क्षेत्र में इन परियोजना की जमीन वन भूमि है, और

- ज्ञात रहे कि यूनिटी मॉल, जो प्रधानमंत्री की वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट पहल का हिस्सा है, तथा राजस्थान मंडपम्, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टॉवर, फाइव स्टार और फोर स्टार होटल्स तथा रिहायशी टावर्स - ये सभी परियोजनाएं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 95 एकड़ रीको भूमि पर अनुमोदित की गई हैं।

ऐसे में इसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर इन परियोजनाओं के निर्माण पर पाबंदी लगाई जाए।

जवाब में राज्य सरकार व रीको की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि संबंधित भूमि 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी। इसकी वैधता

छिपाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। राज्य सरकार ने परियोजना वाली जगह पर कोई पेड़ नहीं काटे हैं और केवल 56 पेड़ों को ही मंजूरी लेकर प्रत्यारोपित किया है। वहीं उनकी संख्या से 10 गुना अधिक पौधे वृक्षारोपण के तौर पर लगाए हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञात रहे कि यूनिटी मॉल, जो प्रधानमंत्री की वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट पहल का हिस्सा है, तथा राजस्थान मंडपम्, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टॉवर, फाइव स्टार और फोर स्टार होटल्स तथा रिहायशी टावर्स – ये सभी परियोजनाएं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 95 एकड़ रीको भूमि पर अनुमोदित की गई हैं।

एफएमडी नेटवर्क लेबारेट्री की समीक्षा बैठक

जयपुर। देश में पशुधन स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा खुरपका मुहपका रोग (एफएमडी) नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए एफएमडी नेटवर्क लेबोरेट्री की 3२वीं वार्षिक समीक्षा बैठक का दो दिवसीय आयोजन आज जयपुर में राज्य रोग निदान केंद्र, पशुपालन विभाग के तत्वावधान में संपन्न हुआ। संयुक्त निदेशक राज्य रोग निदान केंद्र डॉ. लोकेश कुमार शर्मा ने बताया कि ।

प्रसारण निगम का नया पेंशन पोर्टल शुरू

जयपुर। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने पेंशनधारी कर्मचारियों के लिए एक नया ऑनलाइन पेंशन पोर्टल शुरू किया है। अब पेंशन से जुड़ी जानकारी या दस्तावेजों के लिए कर्मचारियों को अब दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे, व घर बैठे ही पेंशन सम्बन्धी सेवायें ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।प्रसारण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से पेंशनधारी कर्मचारी जीवित प्रमाण पत्र, पेंशन से जुड़ी रिपोर्ट, आदेश और भुगतान की जानकारी आसानी से ऑनलाइन देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

एस.एम.एस. अस्पताल में रिश्वतकांड के बाद तीन पुराने कर्मचारी हटाए

–कार्यालय संवाददाता– जयपुर । रिश्वत कांड में पकड़े गए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के डॉ मनीष अग्रवाल के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने स्टोर शाखा में फेरबदल किया है।

जिसमें प्रिंसिपल ने स्टोर शाखा के तीन कर्मचारियों को वहां से हटा कर उनकी जगह नए कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इसके अलावा जो कर्मचारी सालों से स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत था, उसे हटाकर स्टोर इंचार्ज बना दिया गया है। कॉलेज के आदेशों के अनुसार, स्टोर शाखा (उपापन) में कार्यरत जगदीश प्रसाद यादव को हटाकर स्टोर कीपर बनाया गया है।

वहीं केदार प्रसाद स्वर्णकार (सामान्य शाखा) और ऋषि कुमार (संस्थापन शाखा) को स्टोर शाखा (उपापन) में नियुक्त किया गया है। सुरेन्द्र कुमार पाटीदार को स्टोर शाखा (उपापन) से सामान्य शाखा में, प्रमोद सिंह को लेखा शाखा से भंडार शाखा में और धनंजय सिंह को भंडार शाखा से लेखा शाखा में स्थानांतरित किया गया है।

- स्टोर कीपर को हटाकर स्टोर इंचार्ज का सौंपी जिम्मेदारी

इसके अलावा, शंकर लाल जलुथरिया, जो पिछले कई सालों से स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत थे, शंकर लाल जलुथरिया को अब स्टोर इंचार्ज बनाया गया है। बताया जा रहा है कि रिश्वत कांड में पकड़े गए डॉ मनीष अग्रवाल पर 1१ शाखाओं का भार था , वो 1१ शाखाओं का काम देखते थे। डॉ मनीष अग्रवाल के पास आईटी सेल, आरटीआई एवं लीगल सेल, महिला एवं जनाना हॉस्पिटल के सुपरविजन, पैरा क्लिनिक डिपार्टमेंट समेत कई अन्य विभागों का प्रभार था।बताया जा रहा है।

कि मेडिकल कॉलेज में स्टोर शाखा का महत्वपूर्ण रोल है। मेडिकल कॉलेज के अलावा इससे अटैच 7 अन्य अस्पताल में मेडिकल से जुड़े उपकरण तमाम सामान और दवाईयां सप्लाई होती है।

पंचायतीराज विभाग का अधिशाषी अभियंता रामवतार मीणा निकला करोड़ों का मालिक

ए.सी.बी. की टीमों ने ऑपरेशन “भूदेव” चलाकर रामवतार मीणा के जयपुर, करौली, गंगापुर सिटी और उदयपुर में एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया

–कार्यालय संवाददाता– जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने कार्रवाई करते हुए पंचायती राज विभाग इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अधिशाषी अभियंता हाल एसोसियेट प्रोफेसर रामावतार मीणा के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दंड कर ऑपरेशन “भूदेव” चलाया। ए.सी.बी. ने रामवतार के जयपुर, करौली, गंगापुर सिटी व उदयपुर में स्थित एक दर्जन ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया।

एसीबी की सर्व कार्यवाही में करोड़ों रुपये के आलीशान मकान और फार्म हाउस होने की पुष्टि हुई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिमता श्रीवास्तव ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी कि पंचायती राज विभाग,इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अधिशाषी अभियंता हाल एसोसियेट प्रोफेसर रामावतार मीणा द्वारा पद पर रहते हुए रिश्वत प्राप्त की जाकर भ्रष्ट तरीके से भ्रष्टाचार के द्वारा स्वयं एवं अपने परिवारजनों के नाम से अपनी वैध आय से अनुपातिक रूप से अधिक चल-अचल सम्पत्तियां



आरोपी रामवतार मीणा

अर्जित की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए है। इस शिकायत का एसीबी की इंटेलिजेंस टीम ने गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया तथा अधिकारी द्वारा जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली, उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर आवासीय भूखण्ड, प्लॉट्स, फार्म हाउस, कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, अर्जित करने के तथ्य प्रकट हुए। जिस पर विस्तृत रूप से तथ्य संकलित किये गये एवं तथ्यों की जाकर भ्रष्ट तरीके से भ्रष्टाचार के द्वारा स्वयं एवं अपने परिवारजनों के नाम से अपनी वैध आय से अनुपातिक रूप से अधिक चल-अचल सम्पत्तियां

‘कागजों में नहीं धरातल पर काम चाहिए, स्कूलों की मरम्मत का निरीक्षण स्वतंत्र बांडी से भी हो’

–कार्यालय संवाददाता– जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की जर्जर स्कूलों को लेकर कहा है कि उन्हें कागजों में काम नहीं चाहिए, बल्कि काम धरातल पर दिखना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने स्कूलों में कराए जा रहे रिपेयरिंग के काम का निरीक्षण स्वतंत्र बांडी से कराने की मंशा जताते हुए न्यायमित्र सहित सभी पक्षों को इसके लिए नाम सुझाने को कहा है। वहीं अदालत ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को प्रकरण में विद्यार्थियों की मौत के बाद प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंगान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने शपथ पत्र के जरिए

- राजस्थान में जर्जर स्कूलों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को विस्तृत कार्य योजना पेश करने के आदेश दिए
- अदालत ने यह आदेश झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से विद्यार्थियों की मौत के बाद प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंगान पर सुनवाई करते हुए दिए

जर्जर स्कूलों की मरम्मत को लेकर अदालत में जानकारी दी। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि अधिक जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए पांच लाख रुपए का बजट तय किया गया है और आगामी मार्च माह तक काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं शेष स्कूलों में मरम्मत का काम नवंबर, 2026 तक पूरा कर लेंगे। अदालत से कहा कि 5 लाख रुपए में मरम्मत कैसे होगी, लाखों रुपए तो रंग-सफेदी में ही लग जाते हैं। ऐसा लगता

है कि बिना परीक्षण किए सतही तौर पर यह राशि तय की गई है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो और बजट जारी किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों के लिए कुल बजट का 1१.46 फीसदी बजट स्वीकृत किया गया है। अदालत ने मरम्मत के काम के निरीक्षण का काम स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मंशा जताते हुए कहा कि ठेकेदार की गलती से घटनाएं होती हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी से निरीक्षण कराने के बजाए

दिवाली से पूर्व 1५9 आवंटियों को मिले सपनों के घर के आवंटन पत्र

यू.डी.एच. मंत्री झाबर सिंह खर्ा ने लाभार्थियों को सौंपे दस्तावेज

जयपुर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित समृद्धि अपार्टमेंट, जयपुर के 159 पात्र आवंटियों को बुधवार को उनके आवंटन पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने लाभार्थियों को उनके सपनों के घर के दस्तावेज़ सौंपे ।

यह आयोजन प्रताप नगर स्थित

- शहरी सेवा शिविर 2025 में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अब तक 2200 से ज्यादा प्रकरणों को निस्तारण किया

मण्डल के वृ्त प्रथम कार्यालय में चल रहे शहरी सेवा शिविर 2025 अभियान के अंतर्गत किया गया। मंत्री खर्ा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हर सर को छत के संकल्प को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री खर्ा ने सभी 159 आवंटियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और आत्मनिर्भर जीवन की नींव

आयकर विभाग जयपुर रेंज प्रथम का एमटीएस गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय की जयपुर नगर तृतीय जयपुर टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग जयपुर रेंज-प्रथम एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के विष्णु पारीक को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिमता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर को परिव्रादी ने शिकायत दी कि उसकी फर्म साकेत जेम्स के आयकर रिटर्न वर्ष 2014-15 के आयकर अपीलीय



अधिकरण न्यायपीठ जयपुर द्वारा दिये गये फैसले में परिव्रादी के करीब 58 लाख रुपये आयकर विभाग को लौटाने का आदेश जून 2024 में दिये।

“विकसित राजस्थान 2०47” के विजन डॉक्यूमेंट पर काम कर रही भजनलाल सरकार

जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “विकसित भारत 2047” के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी “विकसित राजस्थान 2047” विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भजनलाल सरकार गरीब, युवा, महिला और किसानों के सशक्तीकरण को केन्द्र में रखते हुए इस विज़न डॉक्यूमेंट के मुताबिक काम कर ही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बने इस विज़न डॉक्यूमेंट में राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में विकास के लिए लक्ष्य तय किये गए हैं। इनके अनुरूप प्रदेश में शत-प्रतिशत साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, सुलभ एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जलवायु अनुकूल-जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और कृषि-खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन जैसे आयाम शामिल हैं। दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता को प्राथमिकता दी गई है। चौथी थीम संवर्धक नीति, वित्त और श्रम के विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2०47 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाना चाहिए। अदालत ने महाधिवक्ता को कहा कि आप काम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज भी टीन शेड के नीचे स्कूल संचालित हो रही हैं। सभी जिलों की स्कूलों की ग्रैंडिंग तय हो ताकि, काम को लेकर प्राथमिकता तय हो सके। इस पर अदालत ने कहा कि फिलहाल फोकस सुरक्षा को लेकर है। अदालत मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं स्वतंत्र संस्था से रिपेयरिंग का निरीक्षण स्वतंत्र एजेंसी से कराने के संबंध में सरकार से निर्देश लेने पड़ेगे। एजी ने कहा कि नवंबर माह में केन्द्र सरकार से भी पैसा जारी होगा और उन्हें रोडमप पेश करने के लिए समय दिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को तय करते हुए सभी पक्षों को स्वतंत्र एजेंसी का नाम सुझाने को कहा है।

एक अप्रैल से नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू करने पर मंथन

जयपुर । बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध कराने और पढ़ाई के दिवसों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग आगामी सत्र से एक बड़ा नवाचार करने की ओर अग्रसर है। इसके तहत विभाग अगला शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से आरंभ करने पर विचार कर रहा है। इस बाबत शिक्षा संकुल में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभाग के पदाधिकारियों एवं शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से नए सत्र को एक अप्रैल से शुरू करने पर मंथन किया गया। बैठक में शासन सचिव कुणाल ने इस नवाचार के उद्देश्य बताते हुए कहा कि शैक्षिक सत्र में परिवर्तन से एनईपी 2020 के अनुरूप शिक्षण संचय होगा। इससे न केवल शिक्षण दिवसों की संख्या 180 से बढ़कर 210–220 दिवस तक हो जाएगी, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अधिक समय भी मिलेगा। इसके साथ ही सीबीएसई के शैक्षणिक कैलेंडर से एकरूपता स्थापित होने से विद्यालयों में नामांकन दर में वृद्धि की भी संभावना है।

इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की कथित समस्याओं की भी ध्यान पूर्वक सुना और उनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सतीश्वर जाट ने उपस्थित प्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव आमंत्रित किए और विभाग की ओर से सभी आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया।

वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य

बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस विज़न डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और तकनीक आधारित खेती के माध्यम से उत्पादकता में 40 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में लाने, मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाने, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 10 से कम करने और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। विजन डॉक्यूमेन्ट के अनुसार औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य में एक करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक करने का संकल्प लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्यात को भी पांच गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र को 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार यह विज़न डॉक्यूमेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त को अनुमोदित किया था। दिग्गज हथ मंत्री अमित शाह ने भी13 अक्टूबर को विकसित राजस्थान-2047 की कार्ययोजना विमोचन किया।

इस दस्तावेज को राज्य, संभाग और जिला स्तर पर 1१५6 बैठकों के माध्यम से सुझाव प्राप्त कर तैयार किया गया है। विभिन्न स्तरों पर हितधारकों, विषय विशेषज्ञों, विभागीय अधिकारियों से गहन चर्चा तथा भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता को प्राथमिकता दी गई है। चौथी थीम संवर्धक नीति, वित्त और श्रम के विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2०47 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

ग्रामीण परिवारों को अब तक एक लाख 48 हजार पट्टे वितरित

ड्रोन के माध्यम से 35 हजार 916 गांवों का सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हुआ

जयपुर, 15 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला, युवा, मजदूर और किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार भूमि स्वामित्व के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीणों को पट्टे वितरित कर रही है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य के 2 लाख पात्र ग्रामीण परिवारों को नए स्वामित्व पट्टे वितरित करने की घोषणा की थी, जिसकी पालना में अब तक लगभग 1 लाख 48 हजार 492 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है कि सभी पात्र परिवारों को जल्द ही स्वामित्व कार्ड प्रदान किए जाएं। योजना के अन्तर्गत, ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से अब तक 35 हजार 916 गांवों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं, स्वामित्व कार्ड वितरण एवं सर्वेक्षण कार्यों की सतत निगरानी मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। स्वामित्व योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण एवं



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा घोषित स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य संपत्तियों का सर्वेक्षण व डिजिटलीकरण तथा विवाद रहित संपत्ति स्वामित्व सुनिश्चित करना है।

डिजिटलीकरण तथा विवाद रहित संपत्ति स्वामित्व सुनिश्चित करने के साथ ही, संपत्ति को आर्थिक साधन के रूप में उपयोग में लाना तथा पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली स्थापित करना भी है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में पूरे देश में शुरू की गई स्वामित्व योजना केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रयासों से व्यापक रूप से क्रियान्वित की जा रही है।

पाक व अफगानिस्तान में सीज़ फायर

काबुल/ इस्लामाबाद, 15 अक्टूबर। एकदूसरे के खून के प्यासे बने पाकिस्तान और अफगान तालिबान 48 घंटे के संघर्षविराम पर राजी हो गए हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ये संघर्षविराम बुधवार शाम 6 बजे से शुरू हो गया। इससे पहले, दोनों की लड़ाई सीमा पर सैन्य ठिकानों

■ पिछले हफ्ते से चल रही भारी गोलाबारी के बाद 48 घंटे की शांति रहने की संभावना है।

पर हमले से आगे बढ़ कर अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाने तक पहुंच गई थी। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कई रिहाइशी इलाकों पर हमले किए और काबुल व कंधार में एयरस्ट्राइक कर दी। ये जंग पिछले हफ्ते उस समय तेज हो गई थी, जब पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के कैपों को निशाना बनाते हुए सीमा पार से हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान अफगान तालिबान पर टीटीपी आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगा रहा है, जो 2021 से सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं।

अंता उपचुनाव में जनता सरकार को आईना दिखायेगी- पायलट

पायलट ने टोंक में रनिंग ट्रैक पर सिंथेटिक फ्लोरिंग निर्माण का लोकार्पण किया



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बुधवार को टोंक में रनिंग ट्रैक पर सिंथेटिक पी.यू. फ्लोरिंग निर्माण कार्य का लोकार्पण किया।

■ उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर इस प्रकार का आधुनिक रनिंग ट्रैक बहुत कम जगह देखने को मिलता है।

इस अवसर पर मीडिया के साथियों से बात करते हुए पायलट ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि अंता में उपचुनाव क्यों हो रहा है। माननीय उच्च

अनेक जगह देखा गया है कि अनेक बच्चे एवं नौजवान नशे की लत में पड़ जाते हैं। नशे की लत ऐसी गंभीर समस्या है, जिसका हम सभी को मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। इसी को ध्यान

में रखते हुए हमने मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम, रनिंग ट्रैक का आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, ताकि नौजवान अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकें।

ब्रिक्स ट्रंप की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की अमेरिकी नीति पर नाराजगी जताई है। एक तरह से ट्रंप की यह झल्लाहट ब्रिक्स के आरोपों को ही सही ठहराती है। ब्रिक्स की सदस्यता को अमेरिका के प्रति शत्रुता से जोड़कर, वे पश्चिम की आर्थिक दादागिरी के उसी आख्यान को पुष्ट करते हैं, जिसका ब्रिक्स विरोध करना चाहता है। विडंबना साफ है: धमकियों के जरिए ब्रिक्स को कमजोर करने की कोशिश में ट्रंप इसके अस्तित्व के औचित्य को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका के भीतर घरेलू दशकों के लिए यह बयानबाजी ट्रंप की राजनीतिक छवि को मजबूत करती है, एक ऐसे नेता के रूप में, जो अमेरिकी नौकरियों, डॉलर और राष्ट्रीय गर्व की रक्षा करता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह उनकी

गहरी असुरक्षा को दिखाती है, कि अब एकध्रुवीय (यूनीपोलर) आर्थिक व्यवस्था ढह रही है। डॉलर की “वैश्विक बादशाहत” पर उनका बार-बार जोर देना बीते गौरव के प्रति एक तरह की लालसा जैसा लगता है। ट्रंप का बार-बार यह दोहराना केवल बयानबाजी का अतिरेक नहीं है। यह बदलते वैश्विक आर्थिक समीकरणों को लेकर उनके भीतर की बेचैनी का संकेत है, जहाँ अब आर्थिक ताकत बंट रही है और डॉलर का एकछत्र शासन कमजोर हो रहा है। उनकी यह रक्षात्मक भाषा यह स्पष्ट करती है कि वे ब्रिक्स को केवल एक प्रतिस्पर्धी समूह नहीं, बल्कि उस नए वैश्विक संतुलन के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जो उन्हें और शायद अमेरिका को बेहद असहज बनाता है।

भजन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आनंद मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। मिश्रा 19 अगस्त 2025 को जनसुराज छोड़कर भाजपा में शामिल हुये थे। सूची के अनुसार, हायाघाट से राम चंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है। वहीं, मुजफ्फरपुर सीट से रंजन कुमार गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट मिला है। बनियापुर से केदार नाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह छपरा से श्रीमती छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा (सुरक्षित) से वीरेन्द्र कुमार, बाढ़ से डा. सियाराम सिंह , अगिआंव (सुरक्षित) से महेश पासवान और शाहपुर से राकेश ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है।

वांगचुक की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देरी को हिरासत को चुनौती देने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को केन्द्र सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख और जोधपुर सेंट्रल जेल के पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा था, जब अदालत ने अंगमो की ओर से

दायर याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें वांगचुक की (एनएसए) के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी और उनकी रिहाई की मांग की गई थी। केन्द्र तथा अन्य को नोटिस जारी करते हुए, दो न्यायाधीशों की पीठ ने संबंधित सरकारों से विस्तृत जवाब मांगे थे।

जयपुर सेशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुलिस बल भी तैनात रहा। समय के अभाव का जिक्र कर पुलिस ने बार – बार लोगों से दूर रहने की अपील की पुलिस उपायुक्त ने बताया कि यह इमारत लगभग सात मंजिल की है, इसलिए पूरे परिसर की तलाशी में समय

लगेगा। सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को बार-बार परिसर से दूर रहने के लिए कहा गया। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बारीकी से जांच करने में जुटी है। इसी के साथ साइबर टीम भी आए हुए मेल की आईपी एड्रेस तलाशने में जुटी है।

मृत्युदंड के लिए ज़हर के इंजेक्शन का विकल्प सरकार ने ठुकराया

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मृत्युदंड की सजा के तरीके को बदलने की अपील की गई है, लेकिन केन्द्र सरकार इसे बदलने के लिए तैयार नहीं है। सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया गया कि दोषी को फांसी या जहर का इंजेक्शन में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जा सकता है। हालांकि, केन्द्र ने हलफनामे दायर कर कहा कि ऐसा करना “व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।” इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि केन्द्र समय के साथ विकसित होने को तैयार नहीं दिख रहा है। केन्द्र की ओर से वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने दलील दी कि यह मामला नैतिगटल निर्णय से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि समस्या यह है कि सरकार बदलने को

■ सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और मौखिक टिप्पणी की सरकार बदलने को तैयार नहीं है।

तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बहुत पुरानी प्रक्रिया है, समय के साथ चीजें बदल गई हैं। इस याचिका में मांग की गई है कि फांसी की जगह मौत की सजा जहर का इंजेक्शन, शूटिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर से दी जा सकती है, इन तरीकों से सजायाफता की मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती है। यह जनहित याचिका वकील ऋषि मल्होत्रा ने दायर की है। इसमें फांसी को अत्यधिक पीड़ादायक, अमानवीय और क्रूर बताया गया है। याचिकाकर्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) के तहत “फांसी देकर मृत्युदंड देने को असंवैधानिक” घोषित

करने की मांग की है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, फांसी की प्रक्रिया में दोषी की मृत्यु घोषित करने में लगभग 40 मिनट लगते हैं, जबकि शूटिंग या जहर के इंजेक्शन के जरिए यह प्रक्रिया 5 मिनट में पूरी हो जाती है।

वायु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया विमानों, रॉकेटों या जमीनी मशीनों के माध्यम से की जा सकती है। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित इस मिश्रण में सिल्वर आयोडाइड नैनोकण, आयोडीन युक्त नमक और चट्टानी नमक (रॉक सॉल्ट) शामिल हैं।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी कहा कि जब प्रतिबंध लगाया गया था, तब कोविड-19 के दौरान को छोड़कर वायु गुणवत्ता में बहुत अधिक अंतर नहीं आया था। पीठ ने कहा, अर्जुन गोपाल मामले में आए फैसले के बाद ग्रीन पटाखों की अवधारणा शुरू की गई थी। पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों ने उत्सर्जन में काफी कमी की है। पीठ ने आदेश दिया कि ग्रीन पटाखे केवल निर्धारित स्थानों पर ही फोड़े जा सकते हैं। पीठ ने पटाखे फोड़ने के लिए सुबह छह बजे से सात बजे के तक और रात आठ बजे से 10 बजे तक की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने 10 अक्टूबर को संकेत दिया था कि वह दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है लेकिन एक निश्चित समयावधि के साथ। अदालत ने उस दिन कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध “न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श” क्योंकि ऐसे प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन होता है और न्यायसंगत संतुलन की आवश्यकता है।

जैसलमेर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हुई

जोधपुर, 15 अक्टूबर (कासं)। जैसलमेर में हुए निजी स्लीपर बस अग्निकांड हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया है। हादसे में झुलसे दस साल के यूसुस ने भी आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार, अब भी चार मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इस बीच हादसे में मृत लोगों के परिजनों की डीएनए जांच के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में सैपलिंग शुरू हो गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने बताया कि 24 घंटे के बाद सभी की रिपोर्ट आ जाएगी। महात्मा गांधी अस्पताल में 10 शव लाए गए, एम्स की मोर्चों में रखे गए। वहां भी सैपलिंग हो रही है। सैपल कलेक्शन की प्रक्रिया को लेकर नाराजगी पर हॉस्पिटल अधीक्षक ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वैरिफिकेशन में थोड़ा समय लगता है, जिससे कि कोई गलती न हो। उन्होंने बताया अधिकतम 24 घंटे में शवों की पहचान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे पहले डीएनए की सैपलिंग शुरू होने से पहले परिजनों का

अभी चार मरीज वेंटिलेटर पर, मृत यात्रियों के परिजनों की डीएनए जांच की सैपलिंग शुरू

■ हादसे का शिकार हुए पत्रकार राजेन्द्र चौहान के भाई ने बस मालिक व ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन और पुलिस ने फोन कर सुबह 6 बजे महात्मा गांधी अस्पताल बुलाया, लेकिन यहां घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर नहीं आए। हादसे में जान गंवाने वाले एक मृतक के भाई ने कहा कि हम सुबह से परेशान हो रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में हो रही डीएनए सैपलिंग की व्यवस्था देखने के लिए जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने बताया कि एक मामला ऐसा है, जिसमें मृतक की बूढ़ी मां फलोदी जिले में रहती है। वह यहां नहीं आ सकती। इसके लिए फलोदी जिला प्रशासन से संपर्क कर उनका सैपल

कलेक्ट करवाया जा रहा है। सभी घायलों के इलाज के लिए डॉक्टरों की स्पेशल टीम लगाई गई है। मंगलवार रात करीब 12 बजे से आज सुबह 5 बजे तक 19 शवों से कुल 21 बोन सैम्पल लिए गए और परिजनों के डीएनए सैम्पल लिए गए। बुधवार सुबह तक करीब 10 परिजनों के सैम्पल लिए गए। जिन्हें जोधपुर लैब भेज दिया गया, ताकि डीएनए मैचिंग के बाद शव परिजनों को सौंपे जा सकें। अस्पताल अधीक्षक डॉ। फतेहसिंह भाटी ने बताया कि यहां भर्ती मरीजों में आठ मरीजों की हालत बहुत गंभीर है, जिनको लेकर कुछ नहीं कहा

जा सकता। वर्तमान में चार मरीज ऐसे हैं, जिनको हम जल्द छुट्टी देकर घर भेज सकते हैं। हादसे के बाद, मंगलवार देर रात पहली एफआईआर दर्ज हुई है। हादसे के शिकार पत्रकार राजेन्द्र चौहान के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में केस दर्ज कराया है। बता दें कि जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुए भीषण बस हादसे में 19 यात्रियों की मौत पर ही मौत हो गई थी, जबकि जोधपुर में उपचार के दौरान 79 वर्षीय हर्सेन पुत्र अब्दुल रहमान निक्सी जवांघ ने दम तोड़ दिया। वहीं, बुधवार सुबह 10 वर्षीय यूसुस की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में अब तक कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद प्रशासन की ओर से डीएनए सैम्पलिंग की प्रक्रिया तेजी से चलाई जा रही है।

FLAT 30% TO 50% OFF ON MAKING CHARGES* FOR PREMIUM GOLD – JEWELLERY –

FLAT 50% OFF ON MAKING CHARGES* FOR UN CUT. PRECIOUS & DIAMOND – JEWELLERY –

FLAT 25% OFF ON MAKING CHARGES – FOR EVERY PURCHASE BELOW 30 GRAMS –

TRULY Diwali

FLAT 30% TO 50% OFF ON MAKING CHARGES* FOR PLAIN, TEMPLE & ANTIQUE JEWELLERY

FLAT 50% OFF ON MAKING CHARGES* FOR UN CUT. PRECIOUS & DIAMOND – JEWELLERY –

FLAT 25% OFF ON MAKING CHARGES – FOR EVERY PURCHASE BELOW 30 GRAMS –

OPEN ON ALL DAYS

JAIPUR: TONK ROAD - PH: 96025 33433. VAISHALI NAGAR - PH: 91158 03333 | UDAIPUR - PH: 88756 78133 | JODHPUR - PH: 94133 12103
KOTA - PH: 91459 50033 | BIKANER - PH: 80033 93933 | SRI GANGANAGAR - PH: 74249 65433 | AJMER - PH: 77424 13156

FOR MORE DETAILS CONTACT US ON TOLL FREE NUMBER: 1800 425 7333 | WWW.KALYANJEWELLERS.NET | FOLLOW US ON @KJ BUY ONLINE @ WWW.CANDERE.COM | FOR FRANCHISE ENQUIRIES WRITE TO FRANCHISEE.ENQUIRY@KALYANJEWELLERS.NET